

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 823
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर और एनीमिया का उपचार

823. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कोई प्रयास कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं में कैंसर और एनीमिया के उपचार और जागरूकता के लिए विशेष पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य समतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करना है जो देश भर में ग्रामीण महिलाओं सहित लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। यह मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, निःशुल्क निदान सेवा पहल और निःशुल्क दवा सेवा पहल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, 12.37 करोड़ से अधिक परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या 48.56% है।

(ग): राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं सहित कैंसर रोगियों के उपचार के लिए, एबी-पीएमजेएवाई के स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर में, 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1,961 प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन की 500 से अधिक प्रक्रियाओं के साथ 200 से अधिक पैकेज शामिल हैं।

कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए, भारत सरकार द्वारा गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) शुरू किया गया था, जिसमें अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, प्रारंभिक निदान, प्रबंधन और उचित स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में रेफरल पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, देश भर में 770 जिला एनसीडी क्लिनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू), 372 जिला डे केयर सेंटर और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में, 48 जिला एनसीडी क्लिनिक, 08 कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू), 33 जिला डे केयर सेंटर और 760 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। कैंसर के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस का आयोजन करना और सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल है।

राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले वर्षों में राजस्थान में महिलाओं में स्तन एवं गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की जांच एवं उपचार का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	स्तन कैंसर की जांच	स्तन कैंसर उपचार	गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की जांच	गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर का उपचार
2021-22	1588557	257	156786	781
2022-23	2096447	351	396471	1575
2023-24	933935	793	254212	1788
2024-25	2212228	387	510899	1455

भारत सरकार छह लाभार्थी समूहों - 6-59 महीने के बच्चे, 5-9 साल के बच्चे, किशोर (10-19 साल), प्रजनन आयु वर्ग वाली महिलाएं (15-49 साल), गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की व्यापकता को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम लागू करती है। इसके लिए राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया के प्रबंधन के लिए राज्यों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां और इंजेक्शन फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज (एफसीएम) के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
